Title: Requests the Central Government to stop the atrocities committed by the forest officials on the farmers of Madhya Pradesh.

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के वनाधिकारियों द्वारा वन अधिनियम एवम् उच्चतम न्यायलय के फैसले की आड़ लेकर किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमारेखा पांच किलोमीटर और अधिक बढ़ाकर वहां के किसानों की खेती को नष्ट कर दिया गया है। उनके घरों और गांवों को उजाड़ दिया गया है। इस कारण वहां पर जो हीरे और पत्थरों की खदानें थीं, वह भी बंद हो गई हैं। जिसकी वजह से ५० हजार मजदूर, जो वहां काम करते थे, बेरोजगार हो गए हैं। वहां पर लोगों के पलायन की स्थिति बन रही है। हीरे और पत्थरों की खदानों से जो शासकीय राजस्व प्राप्त होता था, वह भी बंद हो गया है। किसानों के खेत उजड़ गए हैं, चारों ओर आक्रोश फैला हुआ है। मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि वहां के वनाधिकारियों के अत्याचार को रोक कर किसानों की खेती को बहाल किया जाए। जो वास्तविक सीमारेखा है, वन विभाग और राजस्व विभाग की भूमि को भी वन विभाग के खातों में दर्ज कर लिया गया है। अतः असली सीमारेखा को मानकर किसानों को राहत दिलाई जाए।